भाजपा सरकार द्वारा एम्स खोलने का छलावा

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासनकाल में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनाकर उसके अन्तर्गत व एम्स सरीखे बड़े अस्पताल बनाने का शगूफा पेश किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए नरेन्द्र मोदी ने इनकी संख्या 22 करने की घोषणा कर दी, क्योंकि घोषणा करने पर न तो वाजपेयी का कुछ लगा था न मोदी का। इस पूरे खेल का विवरण जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि एम्स है क्या बला?

एम्स अर्थात ऑल इंडिया इस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसेज। यानी यह चिकित्सा विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान है। दिल्ली के 115 एकड़ में बने इस संस्थान की आधारशिला 1952 में रखी गयी थी जो 1956 में, न्यूजीलैंड सरकार के सहयोग से बनकर तैयार हो गया था। इसका उद्देश्य देश के लिए बेहतरीन विशेषज्ञ डाक्टर पैदा करना था। विदित हे कि किसी भी संस्थान में डाक्टर तभी पैदा हो सकते हैं, जब वहां मरीजों का इलाज भी होता हो और मरीजों का इलाज वहीं सबसे बेहतरीन हो सकता है जहां विशेषज्ञ डाक्टर बनाने की प्रक्रिया चल रही हो।

जिस प्रकार अन्य मैडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के चिकित्सीय मापदंडों को नियंत्रित एवं कायदे-कानूनों का पालन कराने के लिए एमसीआई (मैडिकल काउसिंल ऑफ इंडिया) बनाई गई उस तरह का नियंत्रक अथवा रेगुलेटर एम्स के लिए नहीं बनाया गया। यह अपना रेगुलेशन स्वयं करता है। इसके लिए शीर्ष डाक्टरों व कुछ अफसरशाहों की एक गवर्निंग बॉडी है जिसका अध्यक्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री होता है। आज तक ये ज्ञात इतिहास में एम्स के मापदंडों में कोई कमी नहीं आई है अर्थात् इसका स्वत: रेगुलेटरी सिस्टम सही काम कर रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि केन्द्र सरकार ने इसके बजट की कभी कोई सीमा तय नहीं की, जिस उपकरण एवं संसाधनों की इसे जरूरत हो यह प्राप्त कर सकता है। हां मोदी सरकार के कार्यकाल में जरूर इस संस्था को वित्तीय संकट रहा है। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा द्वारा मोटे घोटाले करना है। घोटोलेबाजी में पकड़े जाने से बचने के लिए नड्डा ने एम्स के ईमानदार विजिलेंस अधिकारी चतुर्वेदी को यहां से चलता कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में यहां करोड़ों के घोटाले पकड़ लिये थे। ऐसा भी नहीं है कि नड्डा से पहले घोटाले नहीं होते थे, होते तो थे मगर छोटे पैमाने पर।

मरीजों का इलाज करने व डाक्टरों को सिखाने-पढ़ाने के लिए यहां कुल 42 विभाग है। इनमें सबसे खास आंखों के लिए ओ.पी. सैंटर, हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, कैंसर व ट्रॉमा सैंटर। देश में सबसे पहले हृदय की शल्य चिकित्सा यहीं हुई थी। इसका एक शहरी सेंटर पास ही स्थित ग्रीन पार्क तथा ग्रामीण सैंटर बल्लभगढ़ है। जिसकी तीन छोटी ब्रांचें दयालपुर छायंसा व फतेहपुर बिल्लौच में है एम्स की ओपीडी में प्रतिदिन 15000 (औसतन) मरीज संज्ञान आते हैं। यहां विभिन्न विभागों के कुल 1643 बैड हैं लेकिन दाखिल मरीजों की संख्या यहां 2400-2500 रहती है, जाहिर है एक बैड पर दो और फर्श पर लेटकर अपना इलाज कराने को मजबूर हैं।

इतनी बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों के इलाज एवं डाक्टरों को पढ़ाने-सिखाने के लिए यहां 999 डाक्टरों की फैकल्टी स्वीकृत है। जिसमें से केवल 689 तैनात हैं शेष 304 पद खाली पड़े हैं। यहां एमबीबीएस के लिए पहले 50 लेकिन अब 70 छात्रों को भर्ती की जाती है। परन्तु विशेषज्ञ यानी स्नातकोत्तर शिक्षण हेतु 250 सीटें रखी गयी हैं। यह पढ़ाई 3 वर्ष की होती है। इस प्रकार 250 x 3 = 750 प्रशिक्षु डाक्टर पढ़ने-सीखने के साथ-साथ मरीजों का इलाज करने में विशेषज्ञों का हाथ बंटाते

हैं। काम के अत्यधिक बोझ तथा कई बार उकताये एवं दुखी मरीजों के दुर्व्यवहार के बावजूद यहां के डाक्टर प्राय: संयम नहीं खोते। वे पूरी निष्ठा एवं लग्न से अपने काम में रात-दिन जुटे रहते हैं। इन हालात में बढ़े तनाव के कारण कई प्रशिक्षु डाक्टर आत्महत्या तक कर बैठते हैं।

मरीजों की इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिये डाक्टरों के अलावा ग्रुप ए के लिए स्वीकृत स्टाफ की संख्या तो है 624 परन्तु तैनात है मात्र 406, इसी तरह ग्रुप बी के स्वीकृत पद है 6177 लेकिन मौजूद है केवल 5171, इस ग्रुप में सीनियर रेजीडेंट डाक्टर, नर्सिंग व अन्य पैरा मैडिकल स्टाफ आता है। ग्रुप सी में जहां स्वीकृत पदों की संख्या 4845 हैं वहीं तैनाती केवल 4193 की है। इस प्रकार कुल 12639 स्वीकृत पदों की जगह मात्र 10459 पदासीन लोगों से ही काम चलाया जा रहा है। एक ओर तो भर्ती मरीजों की संख्या स्वीकृत संख्या से डेढ़ गुणा और उन्हें संभालने वाले स्टाफ में 2180 की कमी। ऐसे में मरीज तो दुखी हैं ही संस्थान में कार्यरत तमाम लोग भी भारी तनाव में रहते हैं (ये तमाम आंकड़े वर्ष 2017-18 के हैं जो एम्स की आधिकारिक वेबसाइट से लिये गये हैं।)

इतने बड़े संस्थान के लिये वर्ष 2017-18 में 2967 करोड़ खर्च हुए। 2018-19 के लिये 3298 करोड़ का बजट रखा गया है और 2019-20 के लिये 3599 करोड़ का प्रावधान करने की योजना है। इसमें झज्जर के झाड़सा स्थित एम्स का विस्तार भी शामिल है। विदित है कि 5-6 वर्ष पूर्व जब हरियाणा की हुड्डा सरकार को पता चला कि एम्स अपने विस्तार के लिये किसी उचित जगह की तलाश में है तो उन्होंने तुर्त-फुर्त झाड़सा गांव की 330 एकड़ जमीन अधिग्रहीत करके बिल्कुल मुफ्त एम्स को सौंप दी थी। यहां फिलहाल 750 बैड का कैंसर सैंटर, मां-बच्चा स्वास्थ्य केन्द्र व सामान्य ओपीडी चालू है। शेष सैंटर अभी निर्माणाधीन है।

दिल्ली में स्थित होने के चलते यहां आने वाले मरीजों में सबसे अधिक संख्या स्थानीय मरीजों की 94978 है, इसके बाद यूपी से 31721, बिहार से 19096 तथा हरियाणा से 12688 है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया कि यहां स्थानीय लोगों की अपेक्षा तमाम यूपी, बिहार व बंगाल आदि के मरीज भरे रहते हैं।

अब जानिये भाजपाई एम्स की हकीकत

एम्स के प्रति मरीजों का विश्वास तथा इसकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए इलाज के लिए यहां आने वालों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ इसकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गयी। इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ऋषिकेश, पटना, भोपाल, जोधपुर, रायपुर व भुवनेश्वर में एम्स खोलने का एलान करके जनता को बरगलाने का प्रयास किया था। बीते 20 वर्षों में उक्त 'एम्स' में से एक भी असल एम्स के मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। ये मामूली से बल्कि घटिया स्तर के मैडिकल कॉलेज बनकर रह गये। एम्स का दर्जा दिये जाने से एमसीआई भी इनका निरीक्षण आदि नहीं कर सकतीं इसलिये इनकी खामियों पर कोई अंकुश नहीं। उक्त प्रत्येक 'एम्स' के निर्माण हेतु 830 करोड़ का बजट रखा गया जिसका अभी तक 90 प्रतिशत ही खर्च हो पाया हैं इन तमाम तथाकथित एम्स में से सीटें एमबीबीएस तथा 50 नर्सिंग कॉलेज की है। इनमें 500 बैड का सामान्य तथा 250 बैड का सुपर स्पैशिलिटी अस्पताल रखा गया हैं लेकिन फैकल्टी एवं अन्य स्टाफ तथा उपकरणों के अभाव में चिकित्सा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।

वाजपेयी की स्वास्थ्य सेवा योजना को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार ने फेज-2 में 'एम्स' रायबरेली में खोला। इसका बजट भी 823 करोड़ ही रखा गया लेकिन इसमें से आज खर्च केवल आधा ही हो पाया। इसी से समझा जा सकता है कि वहां कैसा एम्स बन रहा होगा। इसके बाद पुन: आई भाजपा की मोदी सरकार। फेज-4 में मोदी सरकार ने गोरखपुर, नागपुर, गुंटूर, कल्याणी की घोषणा कर दी। इन पर क्रमश 1011 करोड़, 1577 करोड़, 1618 करोड़ व 1754 करोड़ के बजट रखे गये हैं। परन्तु खर्च अीाी तक मात्र 3 प्रतिशत ही किया है।

फेज-5 में कश्मीर, गुहावटी, जम्मू, तमिलनाडू, हिमाचल, बिहार, पंजाब के भंटिडा में कुल 7 एम्स की घोषणा कर डाली। इन सातों में वे केवल एक भंटिडा वाले पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है। बाकी अभी कागजों में भी नहीं है। इनमें से प्रत्येक के लिए बजट का प्रावधान भी मात्र 721 करोड़ रखा गया है जिसका मात्र 3 प्रतिशत अभी तक खर्च हुआ है।

उक्त घोषित एम्स तो बने नहीं और मोदी जी ने छठे फेज की घोषणा करते हुए हरियाणा के मनेठी, झारखंड व गुजरात में भी ऐसे ही फर्जी एम्स खोलने की घोषणा कर डाली। मजे की बात तो यह है कि इन छठे फेज वालों के लिये तो किसी बजट प्रावधान का जिक्र तक भी नहीं किया गया है। दरअसल ये तथाकथित एम्स, जैसे पहले किसी ने नहीं बनाये वैसे ही आगे भी किसी ने नहीं बनाने। इसलिए घोषणा करने में इन घोषणा वीरों का क्या जाता है। उन्हें लगता है कि घोषणा व आधारशिला रखने मात्र से उनकी चुनावी नैया पार लग जायेगी।

गौरतलब है कि घोषणावीर पीएम मोदी ने हिमाचल, कश्मीर, बिहार आदि कुछ राज्यों में जो एम्स स्थापित करने की घोषणा की है, वहां अभी तक यहीं तय नहीं हुआ है कि ये एम्स बनेंगे कौन से स्थान पर? इसी से सिद्ध होता है कि मोदी सरकार ने करना-कराना कुछ नहीं केवल चुनावी बेला में लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास मात्र है।

सरकार की नीयत में खोट इसी बात से नजर आ जाता है कि इन एम्स के निर्माण हेतु वर्ष 2017-18 में 2234 करोड़ का बजट रखा गया है। 2018-19 में 1974 करोड़ तथा 2019-20 में 1139 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। देखने वाली बात यह है कि तथाकथित एम्स की संख्या तो बढ़ती जा रही है और बजट वे भी प्रस्तावित घटता जा रहा है जबकि समय के साथ-साथ महंगाई दर बढ़ती जा रही है।

अवतार-कृष्णपाल की राजनीति

पेज एक का शेष

रही। अभी जब इसने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनते देखा तो भाजपा को नमस्ते कहने में पांच मिनट भी लगाए। 14 फरवरी को यह शख्स कांग्रेस में लौट आया, हालांकि दिखाने के लिए इस पहले यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर के पास ले जाया गया, ताकि गुलाम नबी आजाद का नाम इसके मामले में ज्यादा बदनाम न हो। लेकिन राजबब्बर को आजाद का ही इशारा था कि इसे शामिल करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलवाया जाए। राहुल को चूंकि अवतार सिंह भड़ाना का अतीत नहीं मालूम है इसलिए गुलाम नबी आजाद और राजबब्बर कांग्रेस आला कमान को यह समझाने में कामयाब रहे कि हम गुर्जरों का बड़ा नेता भाजपा से तोड़कर कांग्रेस में ला रहे हैं। यह प्लान पूरी तरह कामयाब रहा। देखा जाए तो तकनीकी रूप से अवतार को यूपी कांग्रेस के जरिए पार्टी में लाया गया और अवतार को यूपी की ही राजनीति में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था लेकिन उसने कांग्रेस में वापसी के साथ ही फरीदाबाद लोकसभा सीट का रास्ता तय कर लिया। कांग्रेस में आने के बाद अवतार ने अपने पुराने मोहरों को फरीदाबाद में जुटाना शुरू कर दिया है।

हालांकि फरीदाबाद की गुर्जर बिरादरी में चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह, ललित नागर और जेपी नागर इस बात पर पूरा जोर लगा देंगे कि अवतार को कांग्रेस का लोकसभा टिकट न मिले लेकिन अवतार तो फिर अवतार है। वह इन चौधरियों के बीच में से रास्ता बनाते हुए हर बार टिकट ले आता है। उसके कांग्रेस में आने से कहीं न कहीं फरीदाबाद कांग्रेस के धुरंधरों का बड़ा तबका खुश नहीं है लेकिन इनके पास वोट नहीं है। वोट जनता को देना है और अवतार को मालूम है कि फरीदाबाद की जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है।

क्या कृष्णपाल गुर्जर से पिंड छूटेगा

मेवला महाराजपुर गांव का रहने वाला कृष्णपाल पढ़ाई के मामले में अवतार से बेहतर है लेकिन मोदी के मंत्रिमंडल में स्थान पाने के बावजूद यह शख्स कुछ कर न सका। इसके नाम से दर्ज है कि इस पूरे कार्यकाल में इसने लोकसभा में फरीदाबाद को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा और न कोई बड़ी समस्या ही उठाई। इसकी कुल उपलब्धि यह है कि यह अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को राजनीति में जमाने में कामयाब रहा और बेटा फरीदाबाद नगर निगम का सीनियर डिप्टी मेयर है। लेकिन जनता से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि गिनाने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है। यमुना पर पुल के शिलान्यास का बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया था लेकिन अभी उस पर काम शुरू होना बाकी है।

केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद के अधिकांश लोग एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में जानते हैं। मीडिया से लेकर अफसरों तक में जहां कहीं भी इसकी दोस्ती है, वे सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में हैं। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट में केंद्रीय मंत्री के हिस्सेदारी की अफवाहें फैलती रहती हैं। हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर कृष्णपाल की सिफारिश के आधार पुलिस और अन्य विभागों में अफसरों की तैनाती करता है। फरीदाबाद की रामलीला तक में इस शख्स के नाम से राजनीति होती है।

कुछ चाटुकारों ने इस शख्स को सौम्य नेता जी के रूप में पेश करने की कोशिश की लेकिन वह कोशिश इस नेता के खिलाफ चली गई। फरीदाबाद को पहली बार ऐसा सांसद और मंत्री मिला जो अपनी बात भाषणों के जरिए सही से रख भी नहीं पाता, संसद में सवाल पूछना तो दूर की बात है।

इस नेता के एजेंट आजकल इस खोज में रहते हैं कि किन किन गांवों में शादियां हो रही हैं, वहां वहां से कृष्पपाल गुर्जर को जरूर बुलाया जाए। कुछ गांवों में तो ऐसे गैंग फैल गए हैं, वे जाकर शादी वाले घरों में सलाह देते हैं कि मंत्री जी को बुलाओ, सीधी पहुंच नहीं है तो हमारे जरिए बुला लो। एक सूटकेस मंत्री जी के साथ चलता है, जिसमें शगुन के लिफाफे हर समय तैयार रहते हैं।

फरीदाबाद के कुछ सेक्टरों में कराए गए नगर निगम के काम को अब कृष्णपाल की उपलब्धि बताकर प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन फरीदाबाद के गांवों की जनता का पेट भरने के लिए कोई उपलब्धि केंद्रीय मंत्री गुर्जर के पास नहीं है। कुल मिलाकर इस शख्स को मोदी के नाम पर जीतने की फिर से उम्मीद है, क्योंकि अपने बूते जीतने की बात इसके मुंह से अभी तक निकली ही नहीं है।

छात्र नेता से सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी कृष्णपाल की उलब्धि को बताती तो जरूर है लेकिन उस उपलब्धि को आम जनता के विकास के लिए इस्तेमाल करने की कला इस शख्स के पास नहीं है।

यह तय है कि भाजपा फिर से कृष्णपाल को ही टिकट देगी। क्योंकि भाजपा में इसके मुकाबले कोई और दावेदार है ही नहीं। फरीदाबाद की जनता का यह दुर्भाग्य है कि एक ऐसा शख्स जिसने पिछले साढ़े चार साल में मक्खी भी नहीं मारी, अब फिर से हमारे बीच वोट मांगने के लिए आने वाला है। तो दूसरी तरफ जनता के पास एक ऐसा विकल्प है जिसने पैसों के दम पर टिकटें खरीदीं और सांसद व विधायक बनता रहा है।